



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2009/चैत्र 23, 1931

No. 54]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2009/CHAITRA 23, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2009

सं. टीएएमपी/45/2005-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, कोलकाता पत्तन न्यास में मौजूदा दरमानों की वैधता को 31 मार्च, 2009 के बाद के लिए विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/45/2005-केओपीटी

कोलकाता पत्तन

आवेदक

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से उसके दरमान (एसओआर) के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए 29 दिसम्बर, 2006 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 34 द्वारा 6 फरवरी 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। संशोधित दरमान आदेश की अधिसूचना से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात 8 मार्च, 2007 से प्रभावी हुए जिसकी वैधता अवधि 31 मार्च 2009 तक है।

2.1. मार्च, 2005 के दिशा-निर्देशों का खंड 3.1.2 महापत्तनों से अपेक्षा करता है कि वे मौजूदा प्रशुल्क की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव उसकी वैधता की समाप्ति के कम से कम 3 महीने पहले अग्रेषित किया जाए।

2.2. महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन करने वाले निजी टर्मिनलों की प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया में अनुसरित मौजूदा दृष्टिकोण/पद्धति के कुछ क्षेत्रों के परिशोधन को अधिसूचित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2008 के अनुच्छेद 5 (i) (ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रशुल्क की वैधता के विस्तारण के अनुरोध पर तब तक कार्यवाही न की जाए जब तक कि प्रशुल्क प्रस्ताव समय पर दाखिल नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त उपयुक्त कारण नहीं दिए जाते हैं। आपवादिक मामलों में भी जहां ऐसे अनुरोधों पर इस प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है, मौजूदा दरों में तदर्थ कटौती किसी भी स्थिति में 3 महीनों से अधिक अवधि के लिए विस्तारित नहीं की जाएगी। विस्तारण इस शर्त के भी अधीन होगा कि विस्तारित अवधि के दौरान प्रोद्भूत अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

3.1. जब इस संबंध में अनुरमरण करवाया गया चूंकि केओपीटी ने अपने दरमान की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव विभिन्न अवधि तक दाखिल नहीं किया था, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2009 द्वारा उसके प्रस्ताव के निरूपण में उसके सामने आई कठिनाईयों को स्पष्ट करते हुए प्रतिसाद दिया था। केओपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:

- (i). केओपीटी अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही में पहले से लगा हुआ है। तथापि, यह जरूरी महसूस किया गया कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण मुख्यतः वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए कार्गो थ्रुपुट के अनुमान और राजस्व के अनुमान की समीक्षा की जाए।

अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2008 (सितम्बर 2008 में मंदी के शुरू होने के पश्चात) तीन महीनों की अवधि के लिए कार्गो थ्रुपुट की समीक्षा नकारात्मक बढ़ोतरी दर्शाती है। तीन महीनों की उक्त अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 1 मिलियन टन तक कार्गो थ्रुपुट में कमी आई है। समान अवधि के लिए कंटेनर यातायात भी नकारात्मक बढ़ोतरी दर्शाता है।

- (ii). कच्चा तेल यातायात केओपीटी के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है। कच्चा तेल दिसम्बर, 2008 से पारादीप से पाइप लाइन के माध्यम से प्रहरित किया जा रहा है। पीओएल यातायात की मात्रा में संभावित कटौती का तत्काल अनुमान लगाना कठिन होगा।

- (iii). पत्तन और गोदा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों और पेंशन का संशोधन पहले से देय है और शीघ्र ही घोषित होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लागत में काफी वृद्धि होगी। अतः इससे प्रशुल्क पर नेटिरियल प्रभाव पड़ेगा।

- (iv). केओपीटी इस प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2008-09 के लिए अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना चाहेगा।

3.2. केओपीटी ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि दरमान के सामान्य संशोधन के लिए उसका प्रस्ताव 30 जून, 2009 तक दाखिल करने की अनुमति दी जाए और उसके मौजूदा दरमान की वैधता को मौजूदा दरों में बिना कोई कटौती किए 6 महीनों के लिए विस्तारित किया जाए।

4. इस स्थिति पर विचार करते हुए कि केओपीटी उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से यातायात का अनुमान लगाने की मुश्किलों का सामना कर रहा है और केओपीटी द्वारा प्रतिवेदित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि वह प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले वर्ष 2008-09 के लिए पत्तन की वास्तविक वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना चाहता है, यह प्राधिकरण केओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता केओपीटी को इस निदेश के साथ 30 सितम्बर, 2009 तक विस्तारित करता है कि वह अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 30 जून, 2009 तक, जैसाकि उसके द्वारा सहमति दी गई है, दाखिल करेगा।

5. 1 अप्रैल 2009 के बाद की अवधि के लिए प्रोद्भूत होने वाली स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से अधिक अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समागोजित किया जाएगा।

अरविन्द कुमार, सदस्य

[विज्ञापन III/4/143/08/असा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2009

No. TAMP/45/2005-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Kolkata Port Trust beyond 31st March, 2009, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

Case No. TAMP/45/2005-KOPT

Kolkata Port Trust

Applicant

**ORDER**

(Passed on this 27th day of March, 2009)

This Authority had passed an Order on 29 December 2006 disposing of the proposal from the Kolkata Port Trust (KOPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR). This Order was notified in the Gazette of India on 6 February 2007 vide Gazette No. 34. The revised Scale of Rates has come into effect from 8 March 2007 after expiry of 30 days from the notification of the Order with a validity period upto 31 March 2009.

2.1 Clause 3.1.2. of the guidelines of March 2005 requires the major ports to forward their proposal for review of the existing tariff at least 3 months before expiry of their validity.

2.2 Paragraph 5(i)(b) of Order dated 30 September 2008 passed by this Authority notifying the refinement of certain areas of existing approach / practice followed in tariff setting exercise of major port trusts and private terminals operating thereat stipulates that the request for extension of validity of the tariff will not be entertained unless sufficient justifiable reasons are advanced for not filing tariff proposal in time. Even in exceptional cases where such requests are entertained by this Authority, an ad-hoc reduction in the existing rates will be effected for the extended period which in any case cannot exceed 3 months. Grant of extension will also be subject to the condition that additional surplus, if any, accrued during the extended period would be fully set off in the next tariff revision.

3.1 When reminded in this regard since the KOPT did not file its proposal for review of its Scale of Rates by the stipulated period, the KOPT vide its letter dated 5 February 2009 has responded explaining the difficulties encountered by it in formulation of its proposal. The main points made by KOPT are summarized below:

- (i). KOPT has already taken up the exercise of submission of its proposal for general revision of its Scale of Rates before the Authority. However, it is felt necessary to review the projection of cargo throughput and estimation of revenue for the years 2009-10 to 2011-12 mainly because of world-wide economic recession.

Review of cargo throughput for three months period October 2008 to December 2008 (after start of recession in September 2008) has shown a negative growth. Cargo throughput has fallen by 1 million tonnes during the said period of three months as compared to the corresponding period of last year. Container traffic for the same period also shows a negative growth.

- (ii). Crude traffic is a major source of revenue for KOPT. Crude is being handled through pipe line from Paradip from December 2008. It would be difficult to envisage immediately the likely reduction in the quantum of POL traffic.
- (iii). Revision of Pay & Allowances and Pension of Port and Dock Employees is already due and likely to be announced shortly. This will result in significant increase in cost. Therefore, it will have a material impact on the tariff.
- (iv). KOPT would like to review its actual financial position for the year 2008-09 before submission of its proposal to the Authority.

3.2. The KOPT has requested this Authority to permit it to file its proposal for general revision of Scale of Rates by 30 June 2009 and extend the validity of its existing Scale of Rates for 6 months without effecting any reduction in the existing rates.

4. Considering the position that the KOPT is encountering difficulties to estimate traffic for the reasons which are beyond its control and taking into account the position reported by KOPT that it wants to review the actual financial position of the port for the year 2008-09 before finalizing its proposal for general revision of tariff, this Authority extends the validity of the existing Scale of Rates of KOPT till 30 September 2009 with a direction to the KOPT to file its proposal for general revision of its Scale of Rates latest by 30 June 2009, as agreed by it.

5. Surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing for the period after 1 April 2009 will be set-off fully, in the tariff to be fixed for the next cycle.

ARVIND KUMAR, Member

[ADVT-III/4/143/08 Exty.]